— Solid Waste Management;

— Development of Market complexes/shopping centres;

— Provision of tourist facilities;

— Development of City/Town Parks;

— Street Lighting for Master Plan roads;

— Slaughter houses;

— Major public amenities like Gardens, Palygrounds, Marriage Halls, Pay and use toilets etc.;

— Cycle/Rickshaw Stands;

— Traffic improvement and management schemes;

— Construction of retaining Walls and slope stability measures in hill station towns; and

Social amenities, especially for the poorer sections.

Development of Guwahati

768. SHRI DRUPAD BORGOHAIN: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether his Ministry has any plan to develop Guwahati;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATRAYA): (a) At present there is no plan under consideration in this Ministry to develop Guwahati.

(b) and (c) The following project profiles were received from the State Government seeking OECF assistance:

(i) Guwahati Metropolitan Storm Drainage Improvement Programme at an estimated cost of Rs. 161 crores;

(ii) Water Supply Scheme for the areas of Guwahati Municipal Corporation at an estimated cost of 400 crores.

OECF, Japan have expressed their inability to include the aforesaid two projects in their loan package during 1998-99. The Department of Economic Affairs may consider posing the above projects for World Bank assistance after Government of Assam submits the revised project proposals duly taking into account the technical comments of this Ministry.

CPWD Service Centres at R.K. Puram

769. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the electric glowsign and mercury bulbs installed at CGHS Dispensary, Sector-12, R.K. Puram, New Delhi have not been working properly since its installation;

(b) when the decision of putting of glowsigns at each dispensary in the said area was taken by Government and total expenditure incurred on it;

(c) whether Engineers (Elect.) posted at CPWD Service Centre are not attending to the complaints properly;

(d) if so, the details thereof and the action taken by Government against the guilty officials; and

(e) by when Government propose to repair the electric glowsigns in the said dispensary for security purposes?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): (a) No, Sir, Minor defects in one of the three glowsign boards and one of the twelve fittings installed at CGHS dispensaries Sec. 12, R.K. Puram, New Delhi were noticed, which have been rectified.

(b) Glowsign boards were installed in January, 1997 at a cost of Rs. 60,000/-

(c) No, Sir, The complaints are being attended to properly.

(d) and (e) The questions do not arise in view of reply at (a) and (c) above.

दिल्ली में गांवों का शहरीकरण

770. **श्री रामजीलालः क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) इस समय दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों में रह रहे लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए दिल्ली के गांवों को शहरीकृत करने का निर्णय लिया है;

(ग) अब तक शहरीकृत गांवों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) शहरी करण किए जाने के लिए शेष गांवों का ब्यौरा क्या है?

शहरीकार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) दिल्ली में गांवों का शहरीकरण जनसंख्या के आधार पर नहीं किया जाता है।

(ग) एम सी डी, एन डी एम सी तथा दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार शहरीकृत गांवों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

एम सी डी	135 गांव
दिल्ली छावनी बोर्ड	6 गांव
एनडीएमसी	1 गांव

(घ) एम सी डी और डीडीए ने सूचित किया है कि क्रमशः 15 तथा 68 गांवों को शहरीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

दिल्ली में नर्सिंग होमों के लिए भूमि

771. **श्री रामजीलालः क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली में नर्सिंग होमों के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित की थी;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरे सहित ऐसी रियायत देने के क्या कारण हैं;

(ग) समाज के गरीब वर्ग के लिए अब तक 25 प्रतिशत पलंग उपलब्ध न कराने वाले नर्सिंग होमों के नाम क्या-क्या है; और

(घ) समाज के गरीब वर्ग के लिए प्रति वर्ष 25 प्रतिशत पलंग उपलब्ध न कराने वाले नर्सिंग होमों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) डीडीए ने सूचित किया है कि दिल्ली में नर्सिंग होम के लिए प्लाटों का आबंटन खुली नीलामी के माध्यम से किया गया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

"सब के लिए आवास" हेतु निर्धारित लक्ष्य

772. **श्री लाला लाजपत रायः क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000 तक "सब के लिए आवास" कराने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या वर्ष 2000 तक लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा और मुम्बई 'दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता और हैदराबाद में आवासीय समस्या के संबंध में क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) शासन के राष्ट्रीय एजेण्डा के भाग के रूप में सरकार का लक्ष्य प्राप्त वर्ष 2 मिलियन अतिरिक्त आवास यूनिटें उपलब्ध कराने का है। इसमें से 7 लाख यूनिटें शहरी क्षेत्र में होंगी।

(ख) 12.02.99 तक 2, 15,769 यूनिटों की मंजूरी दी गई है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) प्रगति की हाल ही में की गई समीक्षा से पता चलता है कि 7 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य तकरीबन पूरा हो जाएगा। तथापि ये अधिकांशतः राज्य सरकारों द्वारा हुडको को समय पर परियोजनाएं प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है। भारत सरकार ने मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई तथा हैदराबाद के बारे में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।